# खुरदरा हुआ खुदरा बाजार

**बदलते वैश्विक माहौल और बढ़ती जरुरतों के हिसाब से अपने घर के दरवाजे विदेशियों के लिए किसी हद तक खोलना तो ठीक हो सकता है लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम मेहमानों को किस कीमत पर अपने यहां बुला रहे हैं। जब विपक्षी दल, व्यापारी संगठन चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि खुदरा बाजार में एफडीआई की मंजूरी से छोटे व्यापारियों और किसानों को भारी नुकसान होगा लेकिन सरकार मुद्दे की गंभीरता और व्यापकता पर विचार करने की बजाए हठ और कुतर्क पर उतारु है। विदेशी कंपनियों की बेहतर रणनीति, प्रबंधन और संग्रहण क्षमता के चलते देशी व्यापार और कारोबारियों पर बीस साबित होंगी ये बात साफ है। विदेशी उत्पादों के प्रति देशवासियों की मानसिकता भी किसी से छिपी नहीं है, ऐसे में यह तय हो गया है कि आने वाले समय में विदेशी कंपनियों देशी हाट और बाजार पर कब्जा जमा लेंगी और देशी उद्योग-धंधे, किसान और खुदरा कारोबारियों के लिये बाजार में कोई जगह नहीं बचेगी। आम उपभोक्ता को भी विदेशी कंपनियों से मनमाफिक दामों पर वस्तुएं खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लबोलुबाब यह है कि सरकार ने देशी खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों का शटर बंद कराने की पूरी तैयारी कर दी है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में पूरा देश भुगतेगा।**

खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी देकर सरकार ने सदियों से चले आ रहे करोडों रुपये के खुदरा भारतीय बाजार को खुरदरा कर दिया है। देश में खुदरा बाजार का टर्न ओवर प्रति वर्ष अरबों रुपये का है, जिससे लाखों करोड़ों परिवार अपना भरण-पोषण करते हैं। सरकार ने यह फैसला लेकर लाखों छोटे, मझोले और पटरी दुकानदारों के पेट में लात तो मारी ही है वहीं देसी उद्योग-धंधो और कुटीर उद्योग का गला घोंटने का काम भी किया है। विपक्ष और व्यापारी संगठन सरकार के इस कृत्य की निंदा कर रहे हैं। निर्णय के पक्ष में सरकार और अर्थशास्त्रियों का अपना तर्क है, उद्योग जगत और संगठनों को इसमें भविष्य की संभावनाएं नजर आ रही हैं लेकिन इन सब के बीच खुदरा बाजार के कारोबारियों छोटे और मझोले व्यापारियों के वर्तमान और भविष्य का क्या होगा इसकी चिंता किसी को नहीं है। कोई विकल्प सुझाए खुदरा बाजार का गला रेतने की सरकारी कोशिश का विरोध तो हो रहा है लेकिन इसे जनसमर्थन नहीं मिल रहा है। खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के बाद अगर किसी पर इस निर्णय का असर पड़ेगा तो वो आम आदमी है जो उपभोक्ता और ग्राहक भी है। लेकिन तमाम दूसरे मुद्दों और मसलों की भांति इस काले निर्णय के विरोध में आम आदमी की चुप्पी हैरान करने वाली है।

देश के कर्ताधर्ता, नीति निर्माता, भविष्य नियंता फिलहाल नफाखोरों, बिचौलियों दलाल और अमेरिकी पूंजीपतियों के दबाव में हैं। एफडीआई की नीति लागू करना इसी दबाव का परिणाम है वाल मार्ट जैसी कंपनिया अपने पक्ष में नीति बनाने के लिये लाबिंग करती हैं। खुंदरा व्यापार के लिए वालमार्ट ने अब तक 650 करोड़ रुपये लॉबिंग पर खर्च किए हैं। एफडीआइ देश के 440 करोड़ खुदरा व्यापारियों, 17 करोड़ किसानों और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली 60 प्रतिशत जनता को तबाह करनेवाली नीति है। महज विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिये विदेशी कंपनियों को अपने यहां बुलाकर देश को महान नहीं बनाया जा सकता। सरकार कहती है कि एफडीआई से 30 प्रतिशत लघु उद्योगों का फयदा होगा, एक करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा, महंगाई कम होगी, किसानों को फायदा मिलेगा, किसानों के बीच से बिचौलिए गायब हो जाएंगे। लेकिन यह कोरी बयानबाजी है। एक वालमार्ट करीब चालीस दुकानों को प्रभावित करेगा। कहा कि देश में खाद्यान के मूल्य और नीति निर्धारण 24 से 26 व्यापारियों के हाथ में हैं। ये वायदा बाजार करते हैं। देश में महंगाई इसी वायदा बाजार से बढ़ी हैं। देश में किसान अपनी मेहनत, पराक्रम से पूरे देश का पेट भर रहे हैं। रिकार्ड खाद्यान उत्पादन हो रहा है, लेकिन वायदा बाजार के कारण महंगाई कम नहीं हो रही।

सरकार अपने निर्णय के पक्ष में सुनहरी, तस्वीर और उजला पक्ष ही रखेगी ये बात लाजिमी है। दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में शुमार भारत में खुदरा व्यापार देश की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है जिस पर सरकार ने हथौड़ा चलाया है। देश में खुदरा व्यापार से जुड़े लाखों व्यापारी बरसों से कम मुनाफे में आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते आ रहे हैं। थोक व्यापार में एफडीआई की मंजूरी सरकार पहले ही दे चुकी है। खुदरा बाजार में देशी कंपनियों के स्टोर ने खुदरा बाजार और व्यापारियों पर सीधे असर डाला है। आकर्षक ऑफर और कम दाम के कारण इन स्टोर में भीर जुटने लगी है, जिसका सीधा असर गली, मोहल्ले की किराया और सब्जी की दुकानों पर दिखने लगा है, वहीं फेरी वाले और गांव देहात से कस्बों और गांवों में शब्जी, फल और अनाज बेचने वाले छोटे व्यापारी पर तो इसका सबसे अधिक असर हुआ है। मल्टी ब्रांड की देसी कंपनियों के सैंकड़ों स्टोर देश भर में खुले हैं जिनमें शहरी इलाके की आबादी का छोटा हिस्सा ही खरीददारी करता है। छोटे शहरों, कस्बों और गांव में बसनेवाली आबादी जो देश की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है अभी भी परंपरागत हाट, बाजार से ही रोजमर्रा की खरीदारी करती है। स्थानीय बाजार और आस-पास के इलाकों से थोक माल खरीदकर खुदरा व्यापार करने वाले कारोबारी स्थानीय जरूरतों और मांग के अनुसार माल खरीदते-बेचते हैं। जिससे कीमतें कंट्रोल में रहती हैं और लोगों को अपनी जरूरत के हिसाब से मनमाफिक उत्पाद भी उपलब्ध हो जाते हैं।

आजादी के 65 वर्षों में सत्ता चाहे जिस भी दल के हाथ में रही लेकिन किसान, छोटे व्यापारी और खुदरा कारोबारियों के बारे में किसी ने भी गंभीरता से नहीं सोचा और उदारवादी नीतियों के नाम पर देसी उद्योग धंधों का नाश करने का काम किया। पिछले छह दशकों में सरकार ने छोटे कारोबारियों के लिए कोई पुख्ता नीति नहीं बनाई कि जिससे देशी उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमा पाते और किसान, उत्पादनकर्ताओं और छोटे कारोबारियों को उनकी मेहनत और लागत का उचित मुनाफा मिल पाता, सरकार का सारा ध्यान कारपोरेट घरानों के हितों पर ही रहा। सत्तासीन दलों ने हमेंशा विदेशी कंपनियों और शक्तिशाली देशों के समक्ष घुटने टेकते हुए उदारवादी नीतियों, विदेशी मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दबाव के तमाम बहाने बनाकर देश के आम आदमी को तो ठगा ही वहीं देशी उद्योग-धंधे और हाट-बाजार को तबाह करने का कुचक्र रचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बदलते वैश्विक माहौल और बढ़ती जरूरतों के हिसाब से अपने घर के दरवाजे विदेशियों के लिए किसी हद तक खोलना तो ठीक हो सकता है लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि हम मेहमानों को किस कीमत पर अपने यहां बुला रहे हैं। जब विपक्षी दल, व्यापारी संगठन चिल्ला-चिल्लाकर कह रहे हैं कि खुदरा बाजार में एफडीआई की मंजूरी से छोटे व्यापारियों और किसानों को भारी नुकसान होगा लेकिन सरकार मुद्दे की गंभीरता और व्यापकता पर विचार करने की बजाए हठ और कुतर्क पर उतारू है।

विदेशी कंपनियों की बेहतर रणनीति, प्रबंधन और संग्रहण क्षमता के चलते देशी व्यापार और कारोबारियों पर बीस साबित होंगी ये बात साफ है। विदेशी उत्पादों के प्रति देशवासियों की मानसिकता भी किसी से छिपी नहीं है, ऐसे में यह तय हो गया है कि आने वाले समय में विदेशी कंपनियों देशी हाट और बाजार पर कब्जा जमा लेंगी और देशी उद्योग-धंधे, किसान और खुदरा कारोबारियों के लिये बाजार में कोई जगह नहीं बचेगी। आम उपभोक्ता को भी विदेशी कंपनियों से मनमाफिक दामों पर वस्तुएं खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लबोलुबाब यह है कि सरकार ने देशी खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों का शटर बंद कराने की पूरी तैयारी कर दी है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में पूरा देश भुगतेगा।

-डॉ. आशीष वशिष्ठ

# पुत्र लालसा में कन्या भ्रूणहत्या

हमारे देश में अल्ट्रासाउण्ड परीक्षण करवाकर हर साल 5 लाख बच्चियां मां के गर्भ में ही मार दी जाती है। पिछले 22 वर्षों के दौरान देश भर में कम से कम एक करोड़ कन्याभ्रूण हत्याएँ की गई है। इसी स्वार्थ ने हमारे समाज को अन्धा, क्रूर और बर्बर बना दिया है। इसी घृणित मानसिकता को मुनाफे में बदलने के लिये पिछले 20-22 सालों में भ्रूण परीक्षण करनेवाले क्लीनिक हर छोटे से लेकर बड़े शहर में कुकरमुत्ते की तरह उग आये हैं। हालांकि जन्म के पहले लिंग-परीक्षण कानूनन जुर्म है फिर भी यह अपराधिक कुकर्म धड़ल्ले से चल रहा है। कन्याभ्रूण हत्या करवाने वालों में सबसे आगे हैं हमारे देश के 'शिक्षित' और 'सम्पन्न' लोग। अगर पहली सन्तान लड़की हुई तो लड़के की चाह में दूसरी और तीसरी बार कन्याभ्रूण हत्या की सम्भावना और भी अधिक होती है।

इसी नृशंसता के कारण लिंग-अनुपात में कमी आ रही है तथा देश के कई इलाकों में शादी की उम्र पार कर चुके कुंवारेपन लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

स्थिति यह होगी कि भविष्य में 1000 लड़कों में 200 लड़कों की शादी नहीं होगी और समाज में महिलाओं से छेड़-छाड़, यौन-उत्पीड़न बलात्कार की घटनाऐं लगातार बढ़ रही हैं। ज्यों-ज्यों लड़कियों की संख्या कम होती जायेगी उसी अनुपात में उनका उत्पीड़न भी बढ़ेगा। ऐसे समाज में हर नज़र भूखे भेड़िये की तरह उनका पीछा करेगी और उन्हें नोचने को तैयार होगी। आधुनिक तरीके से अल्ट्रासाउण्ड, उन सोच वालों के लिये वरदान साबित हुई है, जो पुत्र को वंश चलाने वाला और मां-बाप को मुखाग्नी, तर्पण देकर श्वर्ग पहुंचाने वाला मानते हैं। पहले भी लोग पुत्र लालसा में मन्नत मांगने, झाड़-फूंक, जड़ी-बूटी और साधु-संन्यासियों का सहारा लेते थे। किन्तु ये सब अंधविश्वास सही उपाय नहीं थे। और ये सब के बावजूद लड़कियां जन्म ले ही ले तो यही माना जाता था कि उनकी आराधना में कोई कमी रह गई होगी। लेकिन आधुनिक अल्ट्रासाउण्ड ने पुत्र प्राप्ति की 100 फीसदी गारंटी कर दी है। यह बेटियों के हत्या करने वाले इन धृतराष्ट्रों ने क्या कभी ऐसा सोचा कि ये कैसा पुत्र चाहते हैं। जाहिर है कि वंश बढ़ाने के लिये पुत्र प्राप्ति की चाहत करने वाले लोग इतना भी नहीं समझते कि लाखों कन्याओं को गर्भ में ही हत्या करके अपनी वंश को काट रहे हैं।

यहां लोगों के लिये यह अंधविश्वास है, कि पुत्र की लालसा को अनेक अनुष्ठानों कर्मकाण्डों में पुत्र की उपस्थिति के बिना माता-पिता की मुक्ति नहीं होती। पुत्र लालसा के और भी अनेक कारण हैं। जैसे परिवार का कर्ता-धर्ता होगा, वह सम्पत्ति का स्वामी होगा। वह मुखाग्नि देने वाला और पिण्डदान करने वाला है, यानी वह इस लोक और परलोक में भी माता पिता के श्वर्ग और सुख की गारण्टी है।

हाल में बिहार के मुजफ्फर पुर जिले का जानकी वल्लभ शास्त्री थे जो बहुत बड़े कवि और संस्कृत के विद्वान थे, उन्हें तो बेटी ने ही मुखाग्नी दी थी तो क्या उनकी मृत आत्मा कहीं भटक रही है। ये सब तो ढोंग और पाखण्ड है जिसको पुत्र नहीं है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती।

रामचरित मानस में तुलसीदास ने लिखा है कि गिद्ध जटायू का भगवान राम तो भाई-बान्धव कोई नहीं थे। वहां राम ने ही उसे धर्मपिता मानकर मुखाग्नि दी और उसका पुरा क्रिया-कर्म किया है। और जटायू सुन्दर रूप धारण करके श्वर्ग गया है। यह है औरत को देवी मानने वाले समाज का विद्रूप चेहरा। देवी और कुमारी कन्या की पुजा करने वाला समाज कभी यह नहीं सोचा कि एक तरफ कन्याओं की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है। हमारे हिन्दू धर्म ग्रन्थ के अनुसार दुर्गा सप्तशती की पुष्तक मार्कण्डेय ऋषी ने लिखा है। इन पुष्तक में 750 श्लोक हैं, जिसमें पांचवें अध्याय के हर श्लोक में माता, पुत्री, लक्ष्मी, देवी, दुर्गा, शक्ति सभी रूप में स्त्री से तुलना की गई है।

नवरात्र के अवसर पर नौ दिनों तक नौ कुमारी कन्याओं को देवी मानकर और भोजन कराकर उनके पैर छुकर आशीर्वाद लेते हैं। ब्रह्मा जी का कहना है कि नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीतिता: यानी नौ छोटी कन्या नव दुर्गा है, इनकी पुजा करने से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है।

लोगों को यहां धर्म के इस कर्मकाण्ड का लक्ष्य पितृ सत्ता को सुनिश्चित करना है, इसलिये बेटे की मां को प्रतिष्ठा मिलती है, मातृ पद मिलता है, और बेटी की मां को तरह-तरह की ताने मिलतें है। एक ही घर में दो बहुऐं हैं, एक को बेटा है और एक को सिर्फ बेटी है, तो बेटी वाले को कोई हक देने को तैयार नहीं। उनकी लड़कियां भी अपनी जुबान नहीं खोल सकती। लोगों का यही कहना है, यह तो लड़की है। शादी कर देना है अपनी शसुराल चली जायेगी, इसका यहां क्या हक बनता है। जैसे की गाय बछियों का दान होता है। हमारे समाज में लड़कियां गाय बछियों की तरह दान होती है। उसका कोई हक नहीं बनता, मानों वह अपनी माता-पिता का संतान नहीं है। आज 21 वीं शदी में जहां लड़कियां फाइटर प्लेन चलाने से लेकर अंतरिक्ष में जा रही है और लड़कों से हर क्षेत्र में आगे निकल रही है, वहीं समाज में उनकी स्थिति दोयम दर्जे की बनी हुई हैं। इसका कारण हमारे समाज की पितृसत्तात्मक संग रचना है। हमारे समाज में पुरुषों का आधिपत्य है महिला को एक वस्तु का दर्जा मिला हुआ है उनकी खरीद-फरोख्त होती है। उच्च शिक्षित और ऊंचे ओहदों पर बैठे युवक भी दहेज में मोटी रकम और नाना प्रकार की किमती चिजें चाहते हैं। साथ में कमाऊ बीबी जिसकी कमाई पर हक उनका ही हो। ऐसे समाज में बदलाव कैसे हो सकता है? यह एक बड़ा सवाल है उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षित युवतियां भी दास मानसिकता से मुक्त नहीं है।

**-नीलिमा झा**